बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 217 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 29 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

मंडावली इलाके में युवक की हत्या से हड़कंप, गणपति पंडाल के सामने घोंपा चाकू, आरोपी फरार

नई दिल्ली। दिल्ली के मंडावली इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब राजेंद्र पार्क में गणपति के पंडाल के पास एक युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी गई. एक तरफ जहां गणेश चतुर्थी के मौके पर सुंदर पंडाल और सजावट से माहौल धार्मिक और उत्सव भरा दिख रहा था, वहीं दूसरी ओर पंडाल के पास खून से लथपथ युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पंडाल के बगल में बनी एक बेंच के पास से शव बरामद किया गया. जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान पुलिस को एक जोड़ी जूते भी मिले हैं, जो जांच में अहम सबूत साबित हो सकते हैं. फिलहाल मरने वाले युवक की पहचान नहीं हो सकी है.

बिल पर राष्ट्रपति-राज्यपाल के फैसलों के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते राज्य; केंद्र की दलील

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राय सरकारें उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका (मामला) नहीं कर सकतीं जो राष्ट्रपति या रायपाल ने विधानसभा से पास हुए विधेयकों पर लिया हो, चाहे राय यह कहे कि इससे लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बात चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ के सामने कही। संविधान पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर भी शामिल थे। मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति इस बात पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना चाहती हैं कि क्या राय सरकारें संविधान के अनुछेद 32 के तहत ऐसी याचिकाएं दायर कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति यह भी जानना चाहती हैं कि संविधान के अनुछेद 361 का दायरा क्या है। यह अनुछेद कहता है कि राष्ट्रपति या रायपाल अपने अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। मेहता ने संविधान पीठ को बताया कि इन सवालों पर पहले भी चर्चा हुई है। लेकिन राष्ट्रपति का मत है कि अदालत की स्पष्ट राय जरूरी है, क्योंकि भविष्य में ऐसा मामला फिर उठ सकता है। उन्होंने कहा कि अनुछेद 32 के तहत राय सरकार की ओर से राष्ट्रपति या रायपाल के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। न तो कोर्ट ऐसे मामलों में कोई निर्देश दे सकता है

और न ही इन फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा, अनुछेद 32 का उपयोग तब किया जाता है, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन सांविधानिक ढांचे में राय सरकार खुद मौलिक अधिकार नहीं रखती। राज्य सरकार की भूमिका यह है कि वह अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। सॉलिसिटर जनरल ने आठ अप्रैल के उस फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर रायपाल समयसीमा के भीतर विधेयकों पर फैसला नहीं करते तो राय सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस पर सीजेआई गवई ने कहा कि वह आठ अप्रैल के दो जजों के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यह भी कहा कि रायपाल का किसी विधेयक को छह महीने तक लंबित रखना सही नहीं है। मेहता ने जवाब में कहा कि अगर एक सांविधानिक संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती, तो इसका मतलब यह नहीं कि कोर्ट दूसरी सांविधानिक संस्था को आदेश दे।

इस पर सीजेआई ने कहा, हां, हम समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर यह अदालत ही किसी मामले को 10 साल तक नहीं सुलझाए, तो क्या राष्ट्रपति को कोई आदेश देने का हक होगा? सुनवाई अभी जारी है। 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया था कि अगर कोई रायपाल किसी विधेयक पर अनिश्चितकाल तक फैसला नहीं लेता तो क्या अदालत के पास कोई उपाय नहीं रहेगा? क्या रायपाल की स्वतंत्र शक्ति के चलते बजट जैसे जरूरी विधेयक भी अटक सकते हैं? शीर्ष कोर्ट ने यह सवाल तब उठाया जब कुछ भाजपा शासित रायों ने कहा कि रायपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन रायों ने यह भी कहा कि कोर्ट हर समस्या का हल नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट अभी राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए उस सांविधानिक संदर्भ पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें पूछा गया है कि क्या अदालत रायपाल और राष्ट्रपति को यह निर्देश दे सकती है कि वे विधानसभा से पारित हुए विधेयकों पर तय समयसीमा में निर्णय लें? मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुछेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी कि क्या अदालत राष्ट्रपति को निर्देश दे सकती है कि वह राय विधानसभा से आए विधेयकों पर कब और कैसे फैसला लें।

ट्रंप कायर आदमी है- अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. सीएम ने गुरुवार (28 अगस्त) को दावा किया कि अमेरिका से जो कॉटन (कपास) भारत आता है, उस पर मोदी सरकार ने ड्यूटी हटा दी है. पहले 11 प्रतिशत ड्यूटी थी. केजरीवाल ने कहा, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमें कपास पर 50 पर्सेंट टैरिफ लगाना चाहिए था. लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये किसानों के साथ धोखा है. जब अक्टूबर में हमारे किसानों की कपास मंडी में आएगी, तब उन्हें औने पौने दाम पर बेचनी होगी. गुजरात, पंजाब, विदर्भ, तेलंगाना के किसानों पर असर पड़ेगा. अरविंद केजरीवाल ने कहा, चीन के ऊपर ट्रंप ने 145 प्रतिशत टैरिफ लगाया तो चीन ने भी 125 प्रतिशत टैरिफ लगाया, ट्रंप को झुकना पड़ा. मेक्सिको, कनाडा, यूरोपियन यूनियन हर जगह सरकारों ने ट्रंप का जवाब दिया. ट्रंप एक कायर आदमी है, जो ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ, उसके सामने ट्रंप को झुकना पड़ा. ट्रंप के सामने मोदी जी भीगी बिल्ली बने हुए हैं. पता नहीं क्या मजबूरियां हैं. उन्होंने कहा, आज हमारा देश तरफ से मार खा रहा है. एक तरफ ट्रंप ने 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. इससे हमारी घरेलू इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है. क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट (निर्यात) बंद हो गया. दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अमेरिका से जो सामान आता था, उसपर टैरिफ खत्म कर दिया. अमेरिका का सामान हमारे यहां बिकेगा. हमें तो डबल टैरिफ लगा देना चाहिए था. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ट्रंप ने 50 पर्सेंट टैरिफ लगाया तो हमें 100 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए. हमारी आबादी इतनी है कि कोई भी हमारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता. मोदी जी आप क्यों झुके? ये भारत के सम्मान का मुद्दा है. आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ हैं. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार (28 अगस्त) को कहा, '' निर्यातकों को और अधिक समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार ने कपास (एचएस 5201) पर आयात शुल्क छूट को 30 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है.'' अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना कर 50 प्रतिशत करने का निर्णय बुधवार (27 अगस्त) से लागू हो गया.

यमुना के जलस्तर ने बढ़ाई चिंता, आईटीओ- कश्मीरी गेट समेत इन इलाकों में आ सकती है बाढ़, अलर्ट जारी

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा एक बार फिर गहराने लगा है. लगातार हो रही बारिश और हथनीकुंड से छोड़े जा रहे पानी की वजह से यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है. गुरुवार सुबह 10 बजे यमुना का जलस्तर 205.44 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है. यह स्थिति प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन गई है, यही वजह है कि यमुना के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि हालात को देखते हुए अगले दो-तीन दिनों में यमुना का जलस्तर और भी बढ़ सकता है. बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुताबिक, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से हर घंटे करीब 41 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. वहीं, दिल्ली में वजीराबाद बैराज से 56 हजार क्यूसेक और ओखला बैराज से 46 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इस वजह से यमुना किनारे बसे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है. यमुना बाजार, आईटीओ, कश्मीरी गेट और पल्ला क्षेत्र जैसे निचले इलाकों में पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई है. प्रशासन ने इन जगहों पर राहत सामग्री और टेंट पहुंचा दिए हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे नदी किनारे न जाएं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत बाढ़ नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें. प्रीत विहार के एसडीएम और नोडल अधिकारी संदीप यादव ने बताया कि अगर यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचता है, तो राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए जाएंगे. दिल्ली बोट क्लब में 40 नावें और गोताखोरों की टीमें तैनात की गई हैं. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व और बाढ़ नियंत्रण विभाग पूरी तरह अलर्ट पर हैं. 2023 में भी

यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर के पार पहुंच गया था. तब दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए थे, सड़कें डूब गई थीं और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था. हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी. उस अनुभव से सीख लेते हुए इस बार प्रशासन ने पहले ही इंतजाम कर लिए हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. अगर बारिश तेज हुई, तो यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है. हालांकि अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले हफ्ते में जलस्तर धीरे-धीरे स्थिर हो जाएगा. प्रशासन ने लोगों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे निचले इलाकों या नदी किनारे न जाएं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पर रखें और केवल प्रशासन की जानकारी पर ही भरोसा करें. अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है. राजधानी में आने वाले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं. अगर जलस्तर में और बढ़ोतरी हुई, तो स्थिति गंभीर हो सकती है. फिलहाल प्रशासन सतर्क है और जनता से भी सतर्क रहने की अपील की गई है.

न्यू अशोक नगर में एनकाउंटर, स्पेशल सेल ने रोहित गोदारा गैंग के 2 बदमाश पकड़े; एक के पैर में लगी गोली

नई दिल्ली । दिल्ली के न्यू अशोक नगर में स्पेशल सेल ने मुठभेड़ में रोहित गोदारा गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। एक बदमाश का नाम कार्तिक जाखड़ है और दूसरे का नाम कविश है। इन दोनों बदमाशों का यूएस में बैठे गैंगस्टर हैरी बॉक्सर से जुड़े हैं, जिनके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक, स्पेशल सेल को उनके न्यू अशोक नगर इलाके में इन बदमाशों के आने का इनपुट मिला था। जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने जाल बिछाया और इन्हें पकड़ने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जिसके जवाब में पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मार कर इन्हें काबू किया। उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस ने केशवपुरम इलाके में मुठभेड़ के बाद गला घोटू गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश राजू उर्फ अजय उर्फ कंगारू के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। उसे इलाज के लिए दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके साथ मौजूद बदमाश रवि उर्फ गोटिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू पर 12 जबकि आरोपी रवि पर चोरी,आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, डकैती, छीना-झपटी और सेंधमारी के 7 मामले दर्ज हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने डीयू को दिया U-Special बस का तोहफा, अब छात्रों को मिलेगी यह बड़ी सुविधा

नई दिल्ली।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुशखबरी है. वर्षों से बंद पड़ी U-Special बस सेवा को एक बार फिर शुरू कर दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम छात्रों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का विकल्प प्रदान करेगा. सीएम गुप्ता ने कहा कि सालों से बंद पड़ी U-Special बस की न तो आप सरकार ने और न ही कांग्रेस सरकार ने परवाह की. मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में ही दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार फिर रौनक ला दी है, जहां छात्र यू-स्पेशल बस के जरिए घर से विश्वविद्यालय और वापस घर आ-जा सकेंगे. उन्होंने इसे दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी एक सकारात्मक कदम बताया. U-Special योजना दिल्ली परिवहन विभाग की वह विशेष सेवा है, जिसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके आसपास के इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खास बसें चलाई जाती हैं.

इन बसों का संचालन केवल विश्वविद्यालय के समय-सारणी को ध्यान में रखकर किया जाता है, ताकि छात्र समय पर कॉलेज पहुंच सकें और लौट सकें. दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए U-Special बस सेवा की शुरुआत कई दशक पहले हुई थी. इसका उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित, तेज और किफायती यात्रा का साधन उपलब्ध कराना था. समय के साथ यह सेवा बंद हो गई, जिससे छात्रों को मेट्रो और अन्य महंगे साधनों पर निर्भर रहना पड़ा.

फिर से शुरू होने के फायदे

यात्रा में आसानी– छात्रों को भीड़भाड़ वाली मेट्रो से राहत मिलेगी.

समय की बचत– विश्वविद्यालय के समय के अनुसार चलने वाली बसें छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक होंगी.

पर्यावरण लाभ– इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी आएगी. सीएम गुप्ता ने छात्रों से इस सेवा का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की और इसे दिल्ली विश्वविद्यालय की पुरानी रौनक और ऊर्जा लौटाने वाला कदम बताया. सरकार का कहना है कि आने वाले समय में छात्रों के लिए और भी परिवहन सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जिससे शिक्षा के साथ-साथ यात्रा का अनुभव भी सुगम और सुरक्षित बने.

राजधानी में वकीलों के न्यायिक बहिष्कार का छठा दिन, उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन

नई दिल्ली । दिल्ली के पुलिस थानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति देने के उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों का न्यायिक बहिष्कार छठे दिन भी जारी है। इस दौरान वकीलों ने अपना गुस्सा सड़कों पर निकाला। वहीं, बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों ने एलजी का पुतला फूंका और नारे लगाए। निचली अदालतों के वकीलों के पक्ष में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन जताते हुए बुधवार को काम के दौरान वकीलों को काली पट्टी पहनने का आह्वान किया। वहीं, बुधवार को हुई कोऑर्डिनेशन कमिटी की बैठक में हड़ताल को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव तरुण राणा ने कहा कि शुक्रवार दोपहर 12 बजे उपराज्यपाल भवन के बाहर सभी बार एसोसिएशनों के वकील प्रदर्शन करेंगे। बुधवार को तीस हजारी, रोहिणी, कड़कड़डूमा, द्वारका, साकेत, राउज एवेन्यू और पटियाला हाउस जिला अदालतों में कोई सुनवाई नहीं हुई। जमानत याचिकाएं, गवाही और क्रॉस-एग्जामिनेशन (जिरह) समेत कई महत्वपूर्ण मामले स्थगित कर दिए गए। फरियादी और उनके परिवार वाले अदालत परिसरों के बाहर भटकते नजर आए। वकीलों की अनुपस्थिति के चलते उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। अदालत परिसरों के बाहर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किए। वकीलों ने बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सड़कों पर प्रदर्शन किया। कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों ने कृष्णा नगर रेड लाइट पर जाम लगा दिया था। लगभग दिल्ली की सभी निचली अदालतों में वकीलों ने न्यायिक बहिष्कार के तहत अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने कोर्ट परिसर में पुलिस और सरकारी वकीलों समेत ईडी, सीबीआई और नायब कोर्ट को प्रवेश नहीं करने दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील प्रदीप चौहान ने बताया कि यह नोटिफिकेशन जनता के खिलाफ है। हड़ताल के चलते पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स, ईडी और सीबीआई के अधिकारी भी कोर्ट में नहीं पहुंचे। कई हिरासत संबंधी जरूरी मामले ही सुने गए, लेकिन अधिकांश ट्रायल स्थगित हो गए हैं। उन्होंने बताया, नोटिफिकेशन न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2024 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्कुलर का उल्लंघन करता है। थाने को डेजिग्नेटेड प्लेस बनाना पुलिस को अतिरिक्त शक्ति देगा, जहां क्रॉस-एग्जामिनेशन प्रभावी नहीं हो सकेगा। हमारी हड़ताल फरियादियों के हित में है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ वकीलों का विरोध जारी है, जिसमें पुलिस थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों को साक्ष्य दर्ज करने के लिए निर्दिष्ट स्थान घोषित किया गया है।

ट्रंप का आर्थिक हथियार 50 पर्सेंट टैरिफ बनाम मोदी का प्लान 40

वैश्विक व्यापार जगत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर हिला दिया है। उनके नए टैरिफ आदेशों ने भारत समेत कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। ट्रम्प का सीधा संदेश यही है कि अमेरिकी बाजार को अब विदेशी उत्पादों से बचाया जाएगा और 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत हर उस देश पर शुल्क लगाया जाएगा, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा खड़ी करता है।यह विषय बेहद अहम और गहन है क्योंकि इसमें भारत-अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध, मोदी सरकार की रणनीति, आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास और अमेरिका की वीज़ा नीति के प्रभाव सब कुछ शामिल है। इस कदम से भारत के आईटी सेक्टर, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यातक वर्ग पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे समय में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो रणनीति तैयार की है,उसे मीडिया और नीति- विश्लेषकों ने प्लान 40 का नाम दिया है। यह योजना केवल अमेरिका की टैरिफ चुनौती का जवाब नहीं बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने का खाका भी है। वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में इस समय ट्रंप का 50 पर्सेंट टैरिफऔर मोदी का प्लान 40 सबसे चर्चित विषय बन चुका है। 27 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत पर 50 पर्सेंट का टैरिफ लागू कर दिया है, जिसका सीधा असर भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोकंपोनेंट्स और आईटी सर्विसेज़ सेक्टर पर पड़ा है। अमेरिकीराष्ट्रपति ने यह कदम अचानक नहीं उठाया बल्कि पिछले कई महीनों से वे लगातार भारत को चेतावनी दे रहे थे कि अगर भारत अमेरिकी हितों की अनदेखी करेगा तो उसे आर्थिक हथियार का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि भारत को सबक सिखाना आवश्यक है क्योंकि भारत ने रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखा और साथ ही यूरोप तथा एशिया में नए बाजार खोलकर अमेरिकी दबाव की अनदेखी की। इस एकतरफा फैसले से भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। गौरतलब है कि भारत हर साल अमेरिका को बड़ी मात्रा में वस्तुएं निर्यात करता है। भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी बाजार में उनकी कीमतें बढ़ेंगी और प्रतिस्पर्धा घटेगी। इसका सबसे अधिक असर इन्हीं सेक्टरों पर पड़ रहा है जिनका बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। टेक्सटाइल और गारमेंट्स उद्योग,जो अपने निर्यात का लगभग 30 पर्सेंट अमेरिका भेजते है, अब मुश्किल में हैं। इसी तरह भारतीय फार्मा इंडस्ट्री, जो जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है,उसे भी झटका लगा है।भारतीय आईटीकंपनियां और सॉफ्टवेयर इंजीनियर लंबे समय से अमेरिका में सेवाओं के क्षेत्र में नेतृत्व करते रहे हैं, लेकिन टैरिफ और वीज़ा नीतियों ने उनके भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। ऑटो और इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। साथियों बात अगर हम प्लान 40 को समझने की करें तो, भारत ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए तुरंत रणनीति बनानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने प्रभावित सेक्टरों की पहचान की है और उनके लिए क्रेडिट सपोर्ट, टैक्स रिबेट और एक्सपोर्ट सब्सिडी जैसी राहत योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। टेक्सटाइल उद्योग के लिए यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए ग्राहकों की तलाश की जा रही है। फार्मा इंडस्ट्री को रूस, मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य मिशनों के ज़रिए नए बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आईटी सेक्टर के लिए एशियाई देशों, गल्फ और यूरोप में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।वहीं ऑटो सेक्टर को मेक इन इंडिया और घरेलू ईवी पॉलिसी के जरिए घरेलू बिक्री और उत्पादन बढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है।सरकार का स्पष्ट संदेश है कि भारत किसी एकदेश पर निर्भर नहीं रहेगा और निर्यात का दायरा कई गुना विस्तारित किया जाएगा। इस पूरी रणनीति को प्लान 40 कहा जा रहा है।सरकार का यह प्लान भारत को 40 देशों के साथ नए व्यापारिक गठबंधन औरसमझौते कराने पर आधारित है। इसके अंतर्गत यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए की रफ्तार तेज़ की जा रही है। खाड़ी देशों,विशेषकर यूएई और सऊदी अरब के साथ ऊर्जा और तकनीकी समझौते किए जा रहे हैं।अफ्रीकी महाद्वीप में हेल्थकेयर, फार्मा और टेक्सटाइल मार्केट पर कब्जा जमाने की योजना है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात बढ़ाया जाएगा। साथ ही रूस और चीन के साथ ऊर्जा और रक्षा व्यापार को और मजबूत किया जाएगा। यानी अमेरिका अगर भारत के लिए दरवाजे बंद करता है तो भारत 40 और दरवाजे खोलकर अपने लिए नए रास्ते बनाएगा। साथियों बात अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को हमारे मिशन आत्मनिर्भर भारत के प्रभाव की करें तो,भारत का आत्मविश्वास इस बार पहले से कहीं अधिक है क्योंकि 2019 के बाद से भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए अपनी इंडस्ट्री को मजबूत किया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को लागू किया गया, एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन मिला और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया।

सरकार का मानना है कि टैरिफ हमें चुनौती ज़रूर देंगे लेकिन यही चुनौती हमें स्वदेशी उत्पादन और नए बाजार पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर भी प्रदान करेगी।पीएम ने हाल ही में अपने संबोधन में कहा कि भारत किसी के टैरिफ से नहीं डरता, हम आत्मनिर्भर हैं और दुनियाँ को भारत पर निर्भर रहना होगा। साथियों बात अगर हम अमेरिका की एच1बी वीज़ा नीति को भी सख्त करने की योजना की करें तो अमेरिका ने केवल टैरिफ लगाकर ही भारत को चुनौती नहीं दी बल्कि उसने वैकल्पिक प्लान के तहत एच 1बी वीज़ा नीति को भी सख्त करने की योजना बनाई है। नई शर्तों के अनुसार अब केवल वही लोग एच1बी वीज़ा प्राप्त कर सकेंगे जो अमेरिका में कम से कम 50 लाख डॉलर का निवेश करेंगे। इसका सीधा असर भारतीय आईटी इंजीनियरों, छात्रों और पेशेवरों पर पड़ेगा। भारत से हर साल लाखों युवा अमेरिका जाते हैं लेकिन अब उनके लिए यह रास्ता लगभग बंद हो गया है। हालांकि इस संबंध में मेरा मानना है कि अमेरिका यूं ही एच1बी वीज़ा नहीं देता वह भारतीय उच्च टैलेंट को आकर्षित करने के लिए एच1बी वीज़ा शुरू किया है हम जानते हैं कि भारतीय टैलेंट की अमेरिका में बहुत खास जरूरत है। मेरा तर्क है कि वहां टैलेंट की कमी है और इसलिए उच्चस्तर के टैलेंट की सबसे अधिक जरूरत है,एक रिपोर्ट के अनुसार एच1बी वीज़ा वाले हाईस्किल्ड भारतीय होते हैं, अमेरिकन कर्मचारियों से कहीं ज्यादा सैलरी एच1बी वीजा वालों को मिलती है,वहां एच1बी वीजा वालों को एवरेज 108000 अमेरिकन डॉलर मिलते है,लेकिन अमेरिकी निवासियों को 45760 अमेरिकन डॉलर मिलते है,अगर हाईस्किल्ड टैलेंट की जरूरत अमेरिका को नहीं होती तो क्यों इतनी ज्यादा सैलरी देकर वे भारतीयों को बुलाते? लेकिन अब निवेश की शर्त स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि यह भारत पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। साथियों बात अगर हम इन कदमों से भारत- अमेरिका रिश्तों पर गहरा असर पड़ने की करें तो,पहले से ही रूस-भारतसंबंधों को लेकर अमेरिका असहज था, और अब टैरिफ व वीज़ा पॉलिसी ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है।भारत ने अमेरिका पर निर्भरता घटाने का ऐलान किया है, वहीं अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर टैरिफ और वीज़ा का बोझ डाल दिया है। इसके जवाब में भारत ने 40 देशों के साथ नए व्यापारिक गठबंधन शुरू किए हैं। साफ़ है कि आने वाले समय में भारत- अमेरिका रिश्ते सहयोग और टकराव के मिश्रण से गुजरेंगे।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आज का भारत 1991 वाला भारत नहीं है। उस समय भारत आईएमएफ पर निर्भर था लेकिन आज भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ट्रंप का 50 पर्सेंट टैरिफ भारत को चुनौती देगा लेकिन भारत ने प्लान 40 के जरिए यह संदेश दिया है कि भारत झुकेगा नहीं बल्कि विकल्प तलाशेगा। अमेरिका चाहे एच1बी वीज़ा सख्त करे या टैरिफ बढ़ाए, भारत आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी के जरिए आगे बढ़ेगा। यह पूरा घटनाक्रम यह साबित करता है कि वैश्विक राजनीति अब केवल ताकतवर देशों के इर्द-गिर्द नहीं घूमती बल्कि भारत जैसे उभरते देशों की रणनीति भी भविष्य तय करती है।

सम्पादकीय...

अधिकतर योजनाएं दिखावटी

वैश्विक परिदृश्य में आज हमारा देश खेलकूद के मामले में साधारण दिखाई देता है। बीते वर्षों के ओलंपिक खेलों को देखा जाए तो वहां से हम अधिकतर खेलों में खाली हाथ वापस आते नजर आते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ खेलों जैसे लान टेनिस, कुश्ती, भारोत्तोलन, शूटिंग में ही गिनती के दो चार पदक हमारे देश के हिस्से में आते हैं। हां यह बात अलग है कि गत संपन्न हुए ओलंपिक के भाला फेंक स्पर्धा में व्यक्तिगत रूप से नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक लाकर एक इतिहास रच दिया। एक सौ चालीस करोड़ की जनसंख्या वाले देश में ऐसे कोई भी खिलाड़ी ही नहीं है जो अन्य देशों के खिलाड़ियों से पंगा लेकर पदक ला सके। ठीक ऐसा ही हाल अन्य खेलों के अंतरराष्ट्रीय बड़े आयोजनों में भी है, चाहे वह एशियाई खेल हो या राष्ट्रकुल के खेल स्पर्धा हो। इसके सुधार के लिए हमारी खेल व्यवस्था और हमें आज मूलभूत परिवर्तन के साथ गुजरना होगा। तभी तो उस परिणामों में भी बदलाव आयेगा और पदकों की संख्या में वृद्धि होगी। आज के परिवेश में युद्ध से नहीं, खेल में पदक लाने से देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अतः जरूरी है कि खेल के स्तर को ऊंचा उठाया जाए। वैसे भी खेलकूद जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जिस पर हमें प्रवीणता हासिल करनी है। रोमांच और विविधताओं से भरी खेलों की दुनिया में शिखर पर पहुंचने का सपना हर देश का होता है, कुछ देश जैसे चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, अमेरिका फ्रांस, ब्राजील आदि इस मंजिल को पा लेते हैं और कुछ देशों को प्रायः निराश होकर लौटना पड़ता है। दुर्भाग्य से हमारे देश की गिनती निराश होकर लौटने वाले देशों में होती है। हमारा देश खेल के क्षेत्र में इतना क्यों पिछड़ता जा रहा है, क्या इस सवाल पर किसी ने कभी ध्यान दिया है ? सरसरी तौर पर देखा जाए, तो खेलों कि खराब परिस्थिति के लिए कई कारण नजर आयेंगे। जैसे धन की कमी प्रमुख कारण है। खेल पर हम अपने कुल बजट का आधा प्रतिशत भी खर्च नहीं करते। पैसे के अभाव में खेल सुविधाओं के विस्तार की योजना अधूरी रह जाती है। खिलाड़ियों के पास जब खेलने के लिये आधुनिक सुविधायें ही नहीं रहेंगी तो फिर वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कैसे अपने प्रतिस्पर्धियों के ठहर सकते हैं। वहीं खेल के लिये आवश्यक प्रबंधन ढांचे का अभाव भी एक प्रमुख कारण है। खेल की दुर्दशा का वस्तुतः खेल के विकास और प्रसार की हमारी अधिकतर योजनाएं दिखावटी ज्यादा है। हम अभी तक अपने देश में खेल का एक मजबूत मूलभूत ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकसित नहीं कर पाये हैं। जब तक हम खेलों को गांवों, कस्बों और छोटे-छोटे नगरों तक नहीं ले जायेंगे तब तक खेल के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर शिखर तक पहुंचने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इस संबंध में एक उदाहरण ही काफी है कि रूस में राष्ट्रीय खेलों में मोटे तौर पर आबादी का एक चौथाई हिस्सा शिरकत करता है। यह बहुत निचले स्तर से स्पर्धाएं शुरू हो जाती है, और सुव्यवस्थित रूप में आखिर तक चलती है। हमारे यहां अभी खेलों का ढांचा विकसित ना हो पाने के कारण खेलों में लोगों की भागीदारी बहुत कम है। वहीं चीन जैसा देश जो पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र में खासी प्रगति कर चुका है। आज अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत का चीन एक प्रमुख हस्ती बन चुका है। एशियाई खेलों में तो वह हमेशा ही सिरमौर रहता आया है। आज स्थिति यह है कि क्रिकेट को छोड़कर हमारे देश में खेलों के प्रति रुचि और आकर्षण ना के बराबर है। इसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि खेलों की दुनिया में सफलता के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई खिलाड़ी बिना संघर्ष के जीविकोपार्जन कर सके। यह अविश्वास ही खिलाड़ी के आकर्षण को एक झटके में समाप्त कर देता है। हमारे देश में बहुधा यह भी देखा जाता है कि यदि सभी परिस्थितियों से जूझते हुये खिलाड़ी अंततः शिखर पर पहुंच भी गया तब भी हमारे यहां उसे राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में भाग लेने का मौका खोना पड़ सकता है। यही मूल कारण है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से ज्यादा फिक्र राजनैतिक समीकरण की करने लगता है। इससे होता यह है कि खिलाड़ियों का खेल कौशल भी प्रभावित हो रहा है। उनकी योग्यता को नकारने से उनमें कुंठा और निराशा जन्म ले लेती है, जिसका सीधा प्रभाव उनके प्रदर्शन पर पड़ता है। इन्हीं कारणों को देखते हुए मेजर ध्यानचंद सिंह की जयंती पर्व पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद सिंह ने लगन दृढ़ता और अभाव में भी अपने खेल को जिस तरह से निखारा और सजाया संवारा वह अप्रतिम ही है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ना जाने क्यों हमारे देश की केंद्र सरकारों ने उन्हें आज तक भारत रत्न की उपाधि से वंचित कर रखा है। यह तो जगत विख्यात है हमारे देश का बच्चा-बच्चा जानता है ओलंपिक में जब तक वे खिलाड़ी के तौर पर हिस्सा लेते रहे उन्होंने हॉकी के खेल में स्वर्ण पदकों को लाइन लगा रखी थी। केंद्र की सरकार को इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा और अधिसंख्य जनभावनाओं का आदर करते हुए शीघ्र से शीघ्र हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करना चाहिए। हमारे देश में खिलाड़ियों के सतत अभ्यास और अच्छे प्रशिक्षण की भी कमी है। प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव तो है ही साथ ही अच्छे प्रशिक्षकों की भी कमी है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में होने वाले खेलकूद महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं। खेलकूद का स्तर सुधारने के लिए हम सभी में पूरी निष्ठा का होना बहुत आवश्यक है। बजट प्रावधानों में फेल के लिए खर्च होने वाली राशि में वृद्धि की जाए। ग्रामीण स्तर व निचले स्तर पर खेलकूद गतिविधियों को विशेष बढ़ावा दिया जाए। प्रचार-प्रसार माध्यम ना केवल खेलकूद के समाचारों को पर्याप्त महत्व दें बल्कि इसके साथ ही सफल खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी करें। इस संबंध में सबसे पहली जरूरत एक विस्तृत और सुव्यवस्थित खेल नीति की है। खेलों के विकास के लिये पहली जरूरत एक राष्ट्रीय खेल नीति की है। दूसरी खास जरूरत ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं को निकालकर लाने और फिर उन्हें तराशना की है। यदि हम ऐसा कर ले निश्चय ही एक दिन हम खेल की दुनिया में काफी ऊपर पहुंच सकते हैं।

भारतीय इतिहास के गौरव : छत्रपति संभाजी महाराज

भारत के इतिहास के गौरव छत्रपति संभाजी महाराज डॉ. राकेश कुमार आर्य द्वारा रचित पुस्तक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति है, जो भारतीय इतिहास में छत्रपति संभाजी महाराज के अद्वितीय व्यक्तित्व और उनके योगदान को उजागर करती है। यह पुस्तक न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि इसमें शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के अछूते पहलुओं को बड़ी संजीदगी और गहराई के साथ प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक के लेखक डॉ. राकेश कुमार आर्य ने अपने इतिहास लेखन में जो विशेष दृष्टिकोण अपनाया है, वह इस प्रकार है कि वे अपने इतिहासनायकों के व्यक्तित्व के उन पहलुओं को सामने लाते हैं, जिन्हें सामान्य प्रचलित इतिहास ने अनदेखा किया है। डॉ. आर्य के अनुसार, संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता और भारत को मुगलविहीन राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले देशभक्त भी थे। यह पुस्तक पाठकों को यह समझने में मदद करती है कि संभाजी महाराज ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के विचार को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे भारत का निर्माण करने का संकल्प लिया, जहां मुगलों का प्रभाव समाप्त हो। लेखक ने पुस्तक में यह स्पष्ट किया है कि भारतीय इतिहास में संभाजी महाराज के व्यक्तित्व और उनके योगदान के साथ अन्याय हुआ है। इतिहासकारों और लेखकों ने उनके कृतित्व को सही सम्मान नहीं दिया, और उन्हें मुगल प्रेमी दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत किया। डॉ. आर्य का प्रयास इसे बदलना और संभाजी महाराज की वास्तविक महानता को सामने लाना है। लेखक का मानना है कि संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के गौरव हैं और उनका उचित सम्मान और स्थान स्थापित करना युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है, ताकि वे अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर वर्तमान समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा सकें। पुस्तक का प्रारंभ संभाजी महाराज के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज से होता है और उनके हिंदवी स्वराज्य की विचारधारा को विस्तारपूर्वक समझाया गया है। इसके बाद संभाजी महाराज के बचपन, शिक्षा, विवाह और उनके प्रारंभिक जीवन की घटनाओं का उल्लेख है, जो उनके चरित्र और नेतृत्व क्षमता को उभारते हैं। इसके अतिरिक्त, पुस्तक में उनके साहित्यिक पक्ष, प्रशासनिक दृष्टिकोण और प्रजाहितकारी कार्यों को भी दर्शाया गया है। संभाजी महाराज न केवल युद्धकला में प्रवीण थे, बल्कि एक लेखक और चिंतक के रूप में भी उभरकर सामने आए। पुस्तक में छावा फिल्म और इसके निर्माण का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें संभाजी महाराज की भूमिका विकी कौशल ने निभाई है। फिल्म ने संभाजी महाराज के व्यक्तित्व को नया स्वरूप दिया है और युवाओं में उनके प्रति सम्मान और गौरव की भावना पैदा की है। लेखक के अनुसार, इस प्रकार की फिल्में हमारे अतीत के गौरवशाली पहलुओं से युवाओं को परिचित कराने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। माता जीजाबाई की प्रेरणा और मार्गदर्शन ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों को राष्ट्रवाद और वीरता के मार्ग पर अग्रसर किया। पुस्तक में संभाजी महाराज के युद्ध, उनके बलिदान और धार्मिक आस्थाओं का विशेष उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से उनके बुरहानपुर में कैद होने और औरंगजेब द्वारा दिए गए अत्याचारों के दौरान उनका साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण अत्यंत प्रेरणादायक है।

उन्होंने मृत्यु को भी मातृभूमि की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए स्वीकार किया। यह उनके दृढ़ निश्चय और त्याग की अनूठी मिसाल है। संभाजी महाराज के प्रशासनिक कौशल, मुगलों और पुर्तगालियों के साथ उनके संघर्ष, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध, मराठा-मैसूर संबंध और भारत बचाओ अभियान का उल्लेख भी पुस्तक में किया गया है। इन अध्यायों में उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और भारत के लिए किए गए प्रयासों को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है।

कवि कलश और अन्य साथियों के बलिदान का वर्णन इस बात की पुष्टि करता है कि संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि उनके नेतृत्व में कई वीर सपूतों ने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पुस्तक के लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय इतिहास के साथ अन्याय हुआ है। हमारे वीर और धर्मयोद्धाओं के बलिदानों को भुला दिया गया और सनातन संस्कृति की रक्षा करने वालों को उचित सम्मान नहीं मिला। इस संदर्भ में डॉ. आर्य ने पुस्तक के माध्यम से इसे सही करने का प्रयास किया है। वे चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी अपने अतीत की गौरवशाली घटनाओं से प्रेरणा लेकर अपने राष्ट्र और संस्कृति के प्रति गर्व महसूस करे। पुस्तक में छत्रपति संभाजी महाराज के वंश परंपरा, उनके उत्तराधिकारी और भारतीय इतिहास में उनके योगदान का भी विस्तार से उल्लेख है। लेखक ने संभाजी महाराज को न केवल एक वीर योद्धा, बल्कि एक जीवंत और प्रेरणादायक इतिहास पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके कृतित्व और परिश्रम को स्मारक के रूप में संरक्षित करने का आग्रह लेखक ने विशेष रूप से किया है। अंततः, भारतीय इतिहास के गौरव- छत्रपति संभाजी महाराज- पुस्तक युवाओं और इतिहास प्रेमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। यह पुस्तक न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि यह प्रेरणा, साहस और देशभक्ति की मिसाल भी प्रस्तुत करती है। डॉ. राकेश कुमार आर्य ने संभाजी महाराज के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के उस पक्ष को उजागर किया है, जो सामान्य इतिहास में छिपा रह गया था। पुस्तक का उद्देश्य केवल इतिहास को प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इसे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवंत बनाना है, ताकि वे अपने वीर इतिहास से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की सेवा में योगदान दे सकें। संपूर्ण पुस्तक में लेखक का दृष्टिकोण स्पष्ट और दृढ़ है। उनका उद्देश्य यह है कि संभाजी महाराज को केवल एक मराठा योद्धा के रूप में नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के गौरव और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए। यह पुस्तक वास्तव में इतिहास के प्रति सम्मान और जागरूकता पैदा करने वाली है। डॉ. राकेश कुमार आर्य की यह पुस्तक हमारे इतिहास के एक ऐसे महान नायक छत्रपति संभाजी महाराज को उचित सम्मान और गौरव प्रदान करती है। यह युवाओं में देशभक्ति, साहस और नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में सहायक है। इतिहास के इन गौरवशाली पृष्ठों को वर्तमान पीढ़ी तक पहुँचाना और उन्हें प्रेरित करना इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है।

तीन तलाक कानून के 6 साल

भारत में मुसलमान ही एकमात्र ऐसा समुदाय है जिसके लिए तलाक को आपराधिक और दंडनीय माना जाता है। जब तक के हम अतीत को खंगालकर पिछले छह वर्षों के वर्तमान का आकलन नहीं करते, यह भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न को एक और भयावह याद जैसा प्रतीत हो सकता है। 1937 से 2017 तक, मुस्लिम महिलाओं को तुरंत तीन तलाक देना औपनिवेशिक शरीयत कानून के तहत कानूनी मान्यता के साथ प्रचलन में था। जैसा कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल और इस प्रथा के खिलाफ आजीवन संघर्षरत रहे आरिफ मोहम्मद खान का कहना है यह बात बहुत ही दुखद है कि पवित्र कुरान और पैगंबर मुहम्मद के जीवन तथा उनके कार्यों और प्रामाणिक आचरण द्वारा प्रतिपादित कानून की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। 1985 में जब शाह बानो नाम की एक महिला ने तीन तलाक के एक मामले से जुड़े गुजारे भत्ते के लिए अपने वकील पति के खिलाफ अदालत में मुकदमा जीता तो कुछ उप-संप्रदायों और मुस्लिम के कुछ व्यक्तिगत एजेंटों को छोड़कर, सुन्नी मौलवियों ने न केवल इसका समर्थन किया, बल्कि उन्होंने 'शरीयत बचाओ' के नाम पर मुस्लिम जनता के बीच इसके बचाव के लिए उन्माद भी पैदा किया। इन मौलवियों की दलील का सबसे तीखा देने वाला और दुखद पहलू यह था कि उन्होंने इसे तलाक-ए-बिद्दत (इस्लाम के निर्धारित सिद्धांतों, यानी कुरान और सुन्नत के बाहर विवाह को तुरंत रद्द करने का एक नया तरीका) करार दिया। फिर भी वे इसे शरीयत या इस्लामी न्यायशास्त्र का अभिन्न अंग मानते थे। शाह बानो मामला भारत के आधुनिक काल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसका राजनीतिक लाभ विभिन्न मौलवी और राजनीतिक वर्गों ने उठाया और यह शायद अभी तक कई लोगों के लिए दुखद घाव बना हुआ है। कुल मिलाकर, 1 अगस्त 2019 को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा तत्काल तीन तलाक को दंडनीय अपराध घोषित किए जाने के बाद से पिछले छह वर्षों में क्या बदलाव आया है? पहला, रूढ़िवादी मौलवियों की पकड़ काफी हद तक ढीली पड़ गई है। उन्होंने 2019 के कानून के खिलाफ लगभग 1986 जैसे आंदोलन की धमकी दी थी लेकिन कुछ रैलियों को छोड़कर, शरीयत और संविधान बचाओ अभियान का उनका आह्वान शुरू होने के तत्काल बाद ही विस्मृति के गर्त में समा गया। सभी प्रमुख मुस्लिम संगठनों जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद और कई अन्य ने मुसलमानों, खासकर महिलाओं को नए कानून का विरोध करने और इसे रद्द करने की मांग करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। कुछ हद तक इस मुद्दे ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया लेकिन धीरे-धीरे यह मुद्दा गुमनामी के अंधेरे में चला गया। रूढ़िवादी मौलवियों के इस घुट को हो रहा का सामना इसलिए करना पड़ा कि उन्होंने इसे मुसलमानों की पारिवारिक व्यवस्था के लिए एक सर्वनाश के रूप में देखा था और कहा था कि यह मुसलमानों के घर तबाह कर देगा। इसको अस्तित्व में आए छह साल हो गए हैं और किसी भी मुस्लिम संगठन के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इस कानून ने मुसलमानों के घरों को नुकसान पहुंचाया है।

न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस सप्ताह के अंत में चीन यात्रा से पहले चीन बहुत मीठी-मीठी प्यार भरी बातें कर रहा है। भारत और चीन के बीच रिश्ते कायम होने की 75वीं वर्षगांठ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों की 'पार्टनरशिप' की बात कही है और दोनों के ड्रैगन- हाथी टैंगो (संयुक्त नाच) कहा है। ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाए अनुचित टैरिफ के बाद शी जिनपिंग ने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताते हुए उन्हें और मजबूत करने पर जोर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही की भारत यात्रा के दौरान कहा है कि भारत और चीन को प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं साझेदार की तरह देखा जाना चाहिए। उन्होंने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से कहा है कि मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स जो सदा भारत का विरोधी रहा है और यहां तक कह चुका है कि भारत उनके बराबर देश नहीं है, ने प्रधानमंत्री की यात्रा पर टिप्पणी की है कि इसकी उत्सुकता से इंतज़ार है‟ अगर दूसरा पक्ष दुश्मन बन जाए तो न चीन का न ही भारत का इसमें हित होगा। भारत सरकार की प्रतिक्रिया बहुत सावधानीपूर्वक है क्योंकि मसला केवल 'मतभेद' का ही नहीं।

चीन अतीत में दुश्मनी निभाता रहा है जिसकी एक झलक हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देख कर हटे हैं। जार्ज फर्नांडीज ने रक्षा मंत्री रहते चीन को दुश्मन नम्बर1 कहा था। 2021 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को 'सबसे बड़ा दुश्मन' कहा था। वांग यी को जयशंकर ने बता दिया था कि, भारत और चीन के बीच रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर चुका है। उन्होंने दोनों देशों के बीच, परस्पर आदर, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हितों का मंत्र दिया है। अर्थात भारत सरकार चीन के साथ सुधर रहे रिश्तों पर गदगद नहीं हो रही। फूंक-फूंक कर कदम उठाए जा रहे हैं। यह तो अमेरिका के राष्ट्रपति की मूर्खता है कि दोनों देश नजदीक आ रहे हैं, नहीं तो चीन भारत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। तनाव के कारण कई हैं-

1. हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और चीन के बीच जो मिलीभगत देखने को मिली वह पहली लड़ाइयों में देखने को नहीं मिली थी। पाकिस्तान सामने आकर लड़ रहा था तो चीन पीछे रह कर। विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने लिखा है, चीन इस टकराव में तीसरा अनदेखा पक्ष था। आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ले. जनरल राहुल आर. सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चीन भी एक वैरी था जिससे हम लड़ रहे थे। चीन ने रेडार और सैटेलाइट से प्राप्त जानकारी पाकिस्तान को उपलब्ध करवाई थी। चीन ने पाकिस्तान को न केवल J-10C विमान, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और ड्रोन ही दिए, बल्कि हमारी सैनिक गतिविधियों के बारे सूचना भी देते रहे। चीन में हमारे पूर्व राजदूत अशोक के. कांथा, जिनका कहना है कि हमें चीन के साथ सामान्य रिश्ते करने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, ने भी कहा है कि पहलगाम हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान को न केवल कूटनीतिक समर्थन दिया बल्कि लड़ाई के मैदान में अभूतपूर्व स्तर की साझेदारी नजर आई।

2. चीन सीमा विवाद को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। अब फिर कोई 'एक्सपर्ट कमेटी' का गठन किया गया है जो मामले को देखेगी। यह बाबुओं का पुराना करतब है कि जब किसी समस्या का कोई हल न करना हो तो कमेटी में डाल देते हैं। 2017 का डोकलाम टकराव और 2020 में पूर्व लद्दाख में गलवान में टकराव बताते हैं कि चीन की नजर हमारे क्षेत्र पर है। गलवान को रक्षात्मक करने और हमारे उभार को रोकने के लिए किए गए।

पूर्व कोर कमांडर ले. जनरल सईद अटा हसनैन का कहना है कि चीन का मकसद, भारत की गति को रोकना, उसके आत्मविश्वास को कम करना और उसकी सेना को ऊंची सीमा पर गतिरोध में उलझाए रखना था। यद्यपि भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने से पीछे हट गई हैं, पर 50000 से 60000 सैनिक अभी भी वहां तैनात है क्योंकि चीन अप्रैल 2020 वाली स्थिति पर वापिस लौटने के तैयार नहीं। चीन हमें सदा असुरक्षित रखना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश जिसे वह 'दक्षिण तिब्बत' कहते हैं, पर दावा भी इसी नीति का परिणाम है। बार-बार चीनी नाम देकर वह हमें उत्तेजित करता रहता है। लगभग दो दर्जन बैठकों के बाद भी सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकला, क्योंकि चीन को दिलचस्पी नहीं है।

3. नवीनतम उत्तेजना हमारी सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन द्वारा दुनिया का सबसे विशाल डैम बनाना है। यह डैम वर्तमान किसी डैम से तीन गुना बड़ा होगा। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दाखिल होती है। इसके हमारे लिए बहुत गम्भीर नतीजे निकल सकते हैं क्योंकि जहां निर्माण होना है वह बहुत अस्थिर जगह है और भूचाल की बहुत सम्भावना रहती है। बरसात में बाढ़ की सम्भावना भी बनी रहती है। अगर कभी चीन शरारत करना चाहे तो भारी मात्रा में पानी छोड़ कर नीचे के क्षेत्र को तबाह कर सकता है। भारत इसके निर्माण से प्रभावित होगा, पर हम से कोई बात नहीं की गई। एक प्रकार से हमें और बंगलादेश को बता दिया गया है कि आपके गले पर हमारा अंगूठा होगा। दोनों के बीच नदी पानी को लेकर संवाद का प्रावधान है, पर 2023 के बाद कोई बैठक नहीं हुई। अब जबकि चीन से कई स्तर की वार्ता शुरू हो चुकी है आशा है कि ब्रह्मपुत्र, जिसे चीन 'यारलंग जंगबो' कहता है, पर प्रस्तावित महा डैम पर भी बात होगी और हमारी चिन्ता से उन्हें अवगत करवाया जाएगा।

4. दबाव बढ़ाने के लिए चीन लगातार आर्थिक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। रेयर अर्थ (दुर्लभ खनिज) जो इलैक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्टफोन जैसे उच्च इलैक्ट्रानिक उपकरणों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, का भारत को निर्यात रोक दिया गया था। विशेष फर्टिलाइज़र और सुरंग खोदने वाली मशीनों का भी निर्यात रोक दिया गया था। इलैक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली चीनी कम्पनियों से कहा गया है कि वह भारत को टैक्नोलॉजी ट्रांसफर न करें। यह मामला विदेशी मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री के साथ उठाया था और अब शायद उनकी उपलब्धता शुरू हो जाए, पर इससे चीन की मंशा तो स्पष्ट हो जाती है कि वह हमें असुरक्षित और कमजोर रखना चाहता है। वह जानता है कि एशिया में कोई देश अगर उनका मुकाबला कर सकता है तो वह भारत ही है। जापान जैसे देश पीछे हट गए हैं। चीन के साथ व्यापार में संतुलन पूरी तरह उनकी तरफ झुका हुआ है। हम अपने निर्यात से 100 अरब डॉलर का अधिक आयात वहां से कर रहे हैं। भारत सरकार के प्रयास के बावजूद यह घाटा कम नहीं हो रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा हो रही है। यह भारत के प्रधानमंत्री की सात साल के बाद चीन की यात्रा होगी। अक्तूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच रूस में कज़ान में मुलाकात के बाद रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए थे, पर बीच में ऑपरेशन सिंदूर आ गया जिस दौरान चीन ने हमारे विरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाया था। इसके बावजूद मोदी चीन जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के रवैये के बाद फिर रिश्तों ने करवट ली है। चीन समझता है कि अमेरिका की मूर्खता के बाद मौका है कि भारत को उससे दूर किया जाए। सीएनएन ने भी टिप्पणी की है कि, डोनाल्ड ट्रम्प के नवीनतम टैरिफ युद्ध से यह डर पैदा होता नजर आता है जिसके बारे सोचा भी नहीं जा सकता था,भारत और चीन को सतर्क आलिंगन की तरफ धकेला जा रहा है। पर चीन का रवैया अस्पष्ट है। वह भारत को कुछ शांत तो करना चाहता है, पर जो मुद्दे हमें परेशान करते हैं उन पर कोई रियायत देने को तैयार नहीं। चीन सीमा विवाद स्थाई तौर पर हल करने में रुचि नहीं रखता न ही वह पाकिस्तान की मदद ही बंद करेगा। उद्देश्य केवल अपनी शर्तों पर सीमा विवाद तय करना ही नहीं, उस विवाद के द्वारा वह भारत पर डंडा भी रखना चाहता है। चाहे आजकल वह अच्छी बातें कर रहे हैं, पर इतिहास बताता है कि चीन कभी भी पलट सकता है। दोनों एशियाई महाशक्तियों के बीच अविश्वास वैसे का वैसा है। दोनों के बीच ताकत में जो बड़ा फासला है उसे कम करना है।

चीन के अहंकार का यह ही मुख्य कारण है। इसके लिए हमें आर्थिक सुधार करने हैं, सैनिक क्षमता बढ़ानी है और दोनों देशों के बीच जो टैक्नोलॉजी का फासला है उसे पाटना है।

आर्थिक निर्भरता कम करनी है। जैसे एम्बेसेडर कांथा ने भी लिखा है, यह प्रभाव कि भारत चीन की तरफ बाहरी दबाव के कारण बढ़ रहा को रद्द करने की जरूरत है क्योंकि चीन के साथ कमज़ोरी की स्थिति, सही या कथित, से बात करना कभी भी ठीक नहीं रहता। इसलिए इस बदलाव से बहुत आशा नहीं करनी चाहिए। चीन के साथ अधिक से अधिक झगड़े को सम्भाला जा सकता है, स्थाई शान्ति एक भ्रम है। कई दशकों तक भारत के लिए यह चुनौती होगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पोश्चमबाग एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/0882)

भटनी रेलवे स्टेशन पर डी.आर.एम.का आगमन

(वेबवार्ता)

भटनी देवरिया। भटनी रेलवे स्टेशन पर डी.आर.एम. के आगमन के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने ज्ञापन सौंपकर यात्रियों की समस्याएं सामने रखीं। उन्होंने बताया कि स्टेशन से दक्षिण रेलवे कॉलोनी जाने वाली सड़क पर लगे पोलों पर बल्ब नहीं जलते, जिससे रात्रि में यात्रियों को भारी परेशानी होती है। रेलवे कॉलोनी में पानी की टंकी भर जाने के बाद लगातार पानी बहता है, जिससे जलजमाव की स्थिति रहती है। ज्ञापन में कहा गया कि भटनी स्टेशन उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से जुड़ा है, जहां यात्रियों का लगातार आना-जाना होता है। केवड़ा से नूरीगंज तक सड़क खराब है और बरसात में कीचड़ भर जाने से आवागमन मुश्किल हो जाता है। उत्तर रेलवे कॉलोनी परिसर स्थित दुर्गा मंदिर में

गंदगी की समस्या बनी रहती है। टिकट घर से लगी सड़क को बाईपास से जोड़ने की भी मांग की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा, उपाध्यक्ष दीपक वर्मा, महामंत्री कृष्णादत मिश्रा, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, संजय प्रसाद, अवधेश यादव तथा मीडिया प्रभारी शेषनाथ

भाजपा नेताओं ने दिया ज्ञापन, उठाई यात्रियों की समस्याएं

भाजपा युवा नेता दीपक वर्मा ने गोरखपुर-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस को गोरखपुर की बजाय भटनी से चलाने का आग्रह किया। साथ ही 12166-65 रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 11055-56 गोदान एक्सप्रेस, 11037-38 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस, 15047-48 पूर्वांचल एक्सप्रेस, 15707-08 आम्रपाली एक्सप्रेस और 1534 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के ठहराव की मांग की गई। पीआरएस काउंटर का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक करने का भी सुझाव दिया गया।

रेपपीड़िता के परिजनों ने रेपिस्ट के गिरफ्तारी के लिए सौपा सीओ को ज्ञापन

तमकुहीराज/कुशीनगर।

***सेवरही थाना क्षेत्र के एक गांव में विगत एक सप्ताह पूर्व एक शिक्षिका से हुई थी रेप**
***परिजनों का आरोप रेपिस्ट को बचा रही सेवरही पुलिस**

वृहस्पतिवार के दिन सेवरही थाना क्षेत्र की एक रेप पीडिता के परिजनों ने स्थानीय सपा नेताओं के अगुवाई में रेपिस्ट को गिरफ्तार करने को लेकर एक ज्ञापन तमकुहीराज पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह को सौपा और तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की अन्यथा के स्थिति मे वृहद स्तर पर आन्दोलन प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। सनद हो की सेवरही थाना क्षेत्र के एक गांव की एक लड़की बगल गांव के एक विद्यालय में शिक्षणेत्तर कार्य करती थीं। शिक्षिका पंद्रह अगस्त को झंडारोहण करने अपने विद्यायल पर गई थी, झंडारोहण के बाद शिक्षिका अपने घर आ रही थी। रास्ते में ही चिरंजीवी शिक्षण संस्थान स्कूल पडता है जहां से शिक्षिका पढ़ाई की थी वहा के प्रवंधक/प्रधानाचार्य राहुल तिवारी पुत्र चिरंजीवी तिवारी ने मार्कसीट व टी सी देने के बहाने अपने स्कूल में बुलाया और जबरिया शिक्षिका से दुष्कर्म किया।आरोप है की रेपिस्ट राहुल तिवारी ने दुष्कर्म का वीडियो क्लिप भी बनाया।शिक्षिका को धमकी दिया की उक्त के सम्बंध में किसी को बताओगी तो वीडियो वायरल कर दूंगा,उक्त घटना को शिक्षिका मन मे दबाए रही लेकिन दुसरे दिन रेपिस्ट ने वीडियो को वायरल कर दिया।उक्त प्रकरण में सेवरही पुलिस तो आननफानन में मुकदमा दर्ज रेपिस्टा का मेडिकल परिक्षण भी करा लिया। परिजनों का आरोप है की सेवरही पुलिस भाजपा के एक बड़े नेता के सह पर रेपिस्ट को गिरफ्तार नहीं कर रही ,पीडिता के परिजन उक्त घटना से काफी डरे सहमे हुए हैं। इस सम्बंध में सीओ तमकुही राज राकेश कुमार सिंह से पूछे जाने पर बताया की मामला संज्ञान में है बहुत जल्द रेपिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

वोटर अधिकार यात्रा को बदनाम करने की साज़िश शुरू : वीरेंद्र चौधरी

(वेबवार्ता)

महराजगंज। फरेंदा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा को बदनाम करने की कोशिश शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी की मां पर कथित टिप्पणी इसी का हिस्सा है। भाजपा के लोग राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिए हैं। विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कांग्रेस पार्टी किसी की मां बहन छोड़िए, किसी भी महिला के खिलाफ किसी भी प्रकार की टिप्पणी की सख्त खिलाफ है। अमेठी से पूर्व सांसद रहीं स्मृति ईरानी के बारे में की गई टिप्पणी का कड़ा प्रतिवाद राहुल गांधी ने ही किया था। नोट बंदी के दौरान मोदी ने जब अपनी बुजुर्ग मां को लाइन में खड़ा कर दिया और पत्रकारों द्वारा इस पर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने साफ कहा था कि वे मां हैं,उन पर कोई टिप्पणी नहीं। ऐसे में यह कैसे संभव है कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां पर कोई टिप्पणी करे और राहुल गांधी चुप रहें? विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में हजारों की भीड़ चल रही है,इस भीड़ में जिसने भी ऐसी घटिया टिप्पणी की है,उसकी जितनी भी निंदा की जाय कम है। उन्होंने कहा कि पार्टी स्वयं इसकी जांच करवा रही है। उन्होंने कहा कि उस भीड़ में घुस कर ऐसी टिप्पणी करने वाला कौन है,इसकी गहन छानबीन हो रही है। जरूरी नहीं कि वह पार्टी का कार्यकर्ता हो,यह यात्रा को बदनाम करने की साज़िश भी हो सकती है।

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिये अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

(वेबवार्ता)

तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुये न्यायिक कार्य किया ठप

मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को प्रातःकाल अधिवक्ताओं ने प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की और अदालती काम ठप रहा। दोपहर में बार की बैठक में अध्यक्ष द्वारा बिना वार्ता किये मामले को हल करने के लिखित पत्र देने पर अधिवक्ताओं ने आक्रोश जताया। बैठक में भ्रष्टाचार समाप्त करने के मुद्दे पर वार्ता करने से अधिकारियों द्वारा इनकार करने पर हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि अधिकारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बजाय भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। इसी क्रम में खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकारों पर की गयी कार्यवाही की निन्दा की गयी। तहसील में हर कार्यालय में काम के बदले दाम की कायम परम्परा को खत्म करने के लिये वार्ता करने का निर्णय लिया गया है। बार अध्यक्ष को प्रतिनिधिमण्डल के साथ जाकर वृहस्पतिवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से वार्ता करने के लिये अधिकृत किया गया है। वार्ता के प्रस्ताव को ठुकराने पर हड़ताल करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चन्द्र सिन्हा, हरिनायक तिवारी, अशोक श्रीवास्तव, रघुनाथ प्रसाद, भरत लाल, राम आसरे द्विवेदी, प्रेम बिहारी यादव, आलोक विश्वकर्मा, पवन गुप्ता, भारत सिंह, वेद प्रकाश श्रीवास्तव, सतीश कुमार, दयाराम पाल, जितेन्द्र श्रीवास्तव, रमाशंकर, महेन्द्र श्रीवास्तव सहित अन्य ने अपना विचार व्यक्त किया। अध्यक्षता बार अध्यक्ष हुबेदार पटेल और संचालन महामंत्री नन्दलाल यादव ने किया। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ का प्रदर्शन के बाबत कहना है कि प्रदर्शन बार अध्यक्ष हुबेदार पटेल के विरोध में हुआ है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है।

दो बाइकों की भीषण टक्कर में शिक्षक सहित दो घायल

(वेबवार्ता)

नौपेड़वा, जौनपुर। बक्शा थाना के समीप हाइवे पर गुरुवार दोपहर दो बाइकों में हुई आमने–सामने टक्कर में शिक्षक सहित दोनों बाइक सवार गम्भीर रूप से घायल हो गये। जानकारी के अनुसार बक्शा थाना क्षेत्र के बीवीपुर गांव निवासी 45 वर्षीय इन्दुकान्त मिश्र एवं सड़ेरी गांव निवासी 30 वर्षीय सुरेश घटनास्थल के समीप पहुंचे ही थे कि आमने–सामने से जोरदार टक्कर हो गयी। दोनों घायलावस्था में सड़क पर जा गिरे। स्थानीय लोगों की मदद से 108 नम्बर एम्बुलेंस से नौपेड़वा सीएचसी अस्पताल पहुँचाया गया जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. आलोक रघुवंशी व फार्मासिस्ट लालजी वर्मा ने टीम के साथ प्राथमिक इलाज करके जिला अस्पताल रिफर कर दिया।

बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्कूल वैन संचालन पर डीएम दिव्या मित्तल ने दिखाई सख्ती

देवरिया।

स्कूल बस और वैन से जुड़े हादसों की खबरें अक्सर अभिभावकों की चिंता बढ़ा देती हैं। ऐसे में देवरिया में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने गुरुवार को साफ चेतावनी दी कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में विद्यालय प्रबंधकों संग हुई बैठक में डीएम का सख्त लहजा साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि स्कूल बच्चों के वाहन और उनकी सुरक्षा सीधे-सीधे विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी स्कूल वाहन फिटनेस मानकों पर खरे उतरने चाहिए। खराब हालत वाले वाहन तुरंत बंद किए जाएंगे। ओवरलोडिंग और बिना ड्रेस कोड के ड्राइवर या कंडक्टर मिलने पर प्रबंधन पर कार्रवाई तय है। डीएम ने यहां तक कह दिया कि यदि लापरवाही से कोई हादसा हुआ तो विद्यालय प्रबंधक और वाहन संचालक दोनों पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। अभिभावक लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि कई निजी स्कूल बिना फिटनेस वाले वाहनों और अनट्रेंड ड्राइवरों से बच्चों को ढोते हैं। इससे बच्चों की जान पर हमेशा खतरा बना रहता है। हाल के वर्षों में कई जिलों में स्कूल वैन पलटने या आग लगने की घटनाएं भी हुईं, जिनकी भयावह तस्वीरें लोगों के जेहन में आज भी ताजा हैं। इन्हीं खतरों को देखते हुए डीएम ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं, जिलाधिकारी ने बच्चों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अनूठी पहल की है। उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक विद्यालय में रोड सेफ्टी नोडल टीचर नियुक्त हों और प्रतिदिन प्रार्थना सभा में बच्चों को यातायात नियमों की शपथ दिलाई जाए। उनका मानना है कि बचपन से ही यातायात नियमों का पालन सिखाने से समाज में सड़क सुरक्षा की मजबूत नींव रखी जा सकती है। डीएम दिव्या मित्तल ने विद्यालय प्रबंधकों को भावुक अपील भी की बच्चों की सुरक्षा को अपने बच्चों की तरह समझें। प्रशासन किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं करेगा।

22 केंद्रों पर होगी पीईटी परीक्षा, 10,080 अभ्यर्थी होंगे शामिल

देवरिया।

जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जल्द ही परीक्षा में लगाए जाने वाले केंद्र अधीक्षकों, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिए प्रशासनिक सख्ती बरती जाएगी।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यह परीक्षा जिले में 6 और 7 सितंबर को चार पालियों में आयोजित होगी, जिसमें 10,080 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए जिले में कुल 22 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।

जल्द ही परीक्षा में लगाए जाने वाले केंद्र अधीक्षकों, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिए प्रशासनिक सख्ती बरती जाएगी। परीक्षा दो दिन और चार पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह दोनों दिनों में अभ्यर्थियों को अलग-अलग केंद्रों पर परीक्षा देनी होगी। इस बार केंद्रों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था भी की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। जिले के राजकीय इंटर कॉलेज, अशोक इंटरमीडिएट कॉलेज रामपुर कारखाना, बीआरडी पीजी कॉलेज पुरवां चौराहा, बीआरडी इंटर कॉलेज न्यू कॉलोनी, सेंट्रल एकेडमी मिस्कारी, डीएमटी पब्लिक स्कूल निकट सोमनाथ मंदिर, दीनानाथ पांडेय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीसी रोड, देवरिया सीनियर सेकेंड्री स्कूल देवरिया-गोरखपुर ओवरब्रिज, गंगाप्रसाद इंटर कॉलेज मझगांवा, राजकीय पॉलिटेक्निक औरा-चौरी, जनता इंटर कॉलेज सोनूघाट व रामपुर कारखाना, लाला करमचंद थौंपर इंटर कॉलेज बैतालपुर, महाराजा अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज गरूलपार, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज जलकल रोड, नेशनल पब्लिक स्कूल सोंदा, पीडी एकेडमी कतारी मोड़, एसएसबीएल इंटर कॉलेज गोरखपुर रोड, संत विनोबा पीजी कॉलेज न्यू कॉलोनी, सरस्वती विद्या मंदिर देवरिया खास, शिवाजी इंटर कॉलेज खुखुंदू और यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल कसया बाईपास रोड निकट सोमनाथ मंदिर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

वीरेंद्र सचदेवा का सौरभ भारद्वाज पर तंज, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, चले जाएं मुंबई

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है और दोनों ही दल एक-दूसरे पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते. जहां आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जांच एजेंसियों द्वारा अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में उनसे पूछताछ के बाद, इसे आप के नेताओं के खिलाफ साजिश का हिस्सा बताते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा था, तो वहीं बीजेपी ने भी उन पर पलटवार करते हुए उनकी प्रेसवार्ता को नौटंकी बताते हुए बेरोजगार सौरभ भारद्वाज को अब काम मिल गया है कह कर तंज कसा. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रेसवार्ता को सिरे से खारिज करते हुए इसे आप और इसके नेता की नौटंकी बताया. सचदेवा ने कहा कि, जैसे ही किसी जांच एजेंसी द्वारा आप नेताओं से भ्रष्टाचार पर सवाल पूछे जाते है, वैसे ही वे मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए मंच सजा लेते है.

बेरोजगार नेता को मिला काम-सचदेवा

वीरेंद्र सचदेवा ने तंज कसते हुए कहा कि आखिरकार बेरोजगार सौरभ भारद्वाज को काम मिल ही गया. चुनाव हारने के बाद खुद को बेरोजगार बताने वाले भारद्वाज की छुपी हुई प्रतिभा अब जाकर सामने आई है. बीजेपी अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा, -सौरभ भारद्वाज की प्रेसवार्ताएं इतनी फिल्मी अंदाज में थी कि उन्हें स्क्रिप्ट राइटर बनने पर विचार करना चाहिए, बेकार राजनीति में वक्त गंवाने से अच्छा है मुंबई जाकर पटकथा लिखें, वह उनके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प है.

ड्रामे से ज्यादा जरूरी है न्यायालय

वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा कि आप नेताओं की असली पहचान ही अराजकता, कुशासन और भ्रष्टाचार है. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेताओं को जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते है. लेकिन ड्रामा और मीडिया ट्रायल से उन्हें ज्यादा खुशी मिलती है. उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं पर पहले से ही अस्पताल निर्माण घोटाले सहित गंभीर आरोप लगे हुए है. ऐसे में प्रेसवार्ताओं का मकसद केवल जांच से ध्यान भटकाना है. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, नए-नए सबूत सामने आते जाएंगे.

आप के दूसरे नेताओं से मिलते जुलते है बयान

सचदेवा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब तो आप नेता भविष्यवक्ता भी बन गए है. आज प्रेसवार्ता में भारद्वाज की कही गई बातें उनके नेताओं के उन बयानों से मिलते-जुलते है, जो उनके नेता भी जांच एजेंसी की पूछताछ के दौरान बोला करते थे. लेकिन वे जेल और इसकी गवाह पूरी दिल्ली बन चुकी है.

सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा?

वहीं आप मुख्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले कई सालों से ईडी देश में आतंक फैला रही है. इनके अफसर केंद्र सरकार के साथ मिलकर अलग-अलग राजनेताओं को फंसाने की साजिश करते है.

ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच चीन में शी जिनपिंग और पुतिन के साथ अहम बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बता दें यह उनकी सात वर्षों में पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी साल 2018 में चीन के वुहान में शी जिनपिंग से अनौपचारिक बैठक कर चुके हैं। इस बार की मुलाकात खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब भारत अमेरिका के साथ आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।

अमेरिकी टैरिफ और आर्थिक दबाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों जैसे इस्पात, कपड़ा और कृषि उत्पादों पर भारी टैरिफ बढ़ा दिया है। कई मामलों में ये शुल्क 50 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। इस टैरिफ वृद्धि से भारत के निर्यातकों को काफी नुकसान हो रहा है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में इस मामले पर चर्चा की है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। साथ ही अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर पर भी दबाव बढ़ाया है बता दें जिनमें भारत भी शामिल है। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, पर भारत ने अभी तक रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। इससे अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव बढ़ा है।

चीन के साथ धीरे-धीरे सुधरते रिश्ते

भारत और चीन के बीच हाल के वर्षों में काफी तनाव रहा है, खासकर जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भी तनाव रहा। लेकिन अब दोनों देशों ने शांति कायम रखने के लिए सैन्य और कूटनीतिक बातचीत को शुरू की है। हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारी सैनिक तैनाती अभी भी बनी हुई है, दोनों सरकारें तनाव कम करने की कोशिश कर रही हैं। यह बैठक इस बात का संकेत है कि भारत-चीन संबंधों में अब धीरे-धीरे सुधार की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं।

रूस के साथ गहरे रिश्तों की पुष्टि

रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत के साथ अपने पारंपरिक साझेदारी को मजबूत करने में लगा है। पुतिन और मोदी की बैठक में यह भी चर्चा हो सकती है कि कैसे भारत, रूस और चीन के बीच त्रिपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। मॉस्को के लिए, भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और वे इस साझेदारी को और गहरा करना चाहते हैं। यह बैठक दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा और कूटनीतिक सहयोग के लिए भी महत्वपूर्ण होगी।

संभल कमेटी ने रिपोर्ट सीएम को सौंपी, जिले में बदल गई डेमोग्राफी! सिर्फ 15 फीसदी हिंदू बचे

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश स्थित संभल में वर्ष 2024 के नवंबर में हुए दंगे के बाद गठित न्यायिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी. कमेटी ने 28 अगस्त 2025, गुरुवार को रिपोर्ट सौंपी. इस रिपोर्ट में संभल की आबादी और डेमोग्राफी को लेकर कई चौंकाने वाले दावे हुए है. 450 पन्ने की इस रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर को लेकर भी जानकारी दी गई है. संभल कमेटी की रिपोर्ट से आबादी को लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं. सूत्रों के अनुसार हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिले है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आजादी के वक्त सन् 1947 में 45 फीसदी हिंदू थे, अब सिर्फ 15 फीसदी -20 फीसदी बचे है. सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि दंगे, तुष्टिकरण की राजनीति ने संभल की जनसांख्यिकी बदल दी.

संभल कमेटी रिपोर्ट में और क्या?

संभल में हुई हिंसा के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग 450 पन्नों की रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर को हुई हिंसा का जिक्र है, बल्कि संभल के इतिहास में हुए दंगों की संख्या और उन दंगों के दौरान क्या-क्या हुआ, इसका भी विवरण दिया गया है. रिपोर्ट के

कब-कब हुए दंगे; 450 पन्नों में दर्ज पूरा इतिहास

अनुसार आजादी के वक्त संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55फीसदी मुस्लिम और 45 फीसदी हिंदू रहते थे. वर्तमान में लगभग 85 फीसदी मुस्लिम और 20 फीसदी हिंदू रहते हैं. संभल में 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019 में दंगे हुए थे. रिपोर्ट के अनुसार आजादी के बाद से कुल 15 दंगे संभल में हुए.

संभल में आतंकी संगठन एक्टिव- रिपोर्ट

सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया कि संभल कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है. अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन संभल में पैर पसार चुके हैं.

संभल हिंसा पर गठित न्यायिक आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड IAS अमित मोहन, रिटायर्ड IPS अरविंद कुमार जैन शामिल थे.बता दें 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा हुई थी. हिंसा के बाद ही इस न्यायिक कमेटी का गठन हुआ था.

65 लाख गरीबों के मताधिकार पर संकट? राहुल गांधी बोले- बीजेपी-ईसी का पर्दाफाश!

सीतामढ़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि बिहार की मतदाता सूचियों से 65 लाख गरीब और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। 'वोटर अधिकार यात्रा' के तहत सीतामढ़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग को अपने वोट का अधिकार ''छीनने'' की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा, ''हमने भाजपा और चुनाव आयोग का पर्दाफाश कर दिया

-: बिहार चुनाव :-

है, जो वोट चुराने में लिप्त थे... उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में ऐसा किया। अब वे इसे बिहार में दोहराना चाहते हैं, जो हम उन्हें नहीं करने देंगे।'' राहुल ने दावा किया कि आने वाले महीनों में वह ''वोट चोरी'' के बारे में और सबूत पेश करेंगे। रैली से पहले उन्होंने इलाके के प्रसिद्ध जानकी मंदिर में दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इससे एक दिन पहले बिहार के कटिहार में राहुल गांधी अपनी पतलून ऊपर चढ़ाए पानी से भरे एक खेत में उतरे और झुककर गंदे पानी से मखाने की फलियां तोड़ने लगे। उनके आस-पास किसान मखाने की खेती की कठिन प्रक्रिया का प्रदर्शन कर रहे थे–यह काम लगभग पूरी तरह से नदी किनारे बसे गरीब समुदायों द्वारा किया जाता है।

राहुल ने सवाल पूछे, ध्यान से सुना, गंभीरता से सिर हिलाया और तुरंत महसूस किया कि किसान अपनी इतनी मेहनत के बावजूद मुख्य लाभार्थी नहीं थे। बाद में उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें लिखा था- मखाना बिहार के किसानों की पसीने और मेहनत की उपज है। यह हजारों में बिकता है, लेकिन उनकी कमाई चंद पैसों की होती है जबकि सारा मुनाफा बिचौलियों को जाता है। हमारी लड़ाई इस अन्याय के खिलाफ है कड़ी मेहनत और कौशल के लिए पुरस्कार का अधिकार मजदूर का होना चाहिए।

जब तक मैं जिंदा हूं, किसी को लोगों का मताधिकार नहीं छीनने दूंगी : ममता बनर्जी

कोलकाता। बिहार के बाद अन्य राज्यों में गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सियासी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इसे लेकर लगातार मोदी सरकार और चुनाव आयोग का विरोध कर रहा है। इस बीच, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुले शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित करते कहा कि वह किसी को भी लोगों का मताधिकार नहीं छीनने देंगी। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करने के लिए देश भर से पश्चिम बंगाल में 500 से ज्यादा टीमें तैनात की है। रैली में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अब आपको खुद जांच करनी होगी कि आपका नाम अभी भी मतदाता सूची में है या कट गया है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, किसी को भी लोगों का मताधिकार नहीं छीनने दूंगी।सीएम बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग राज्य सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है। उन्होंने दावा किया कि आयोग का अधिकार क्षेत्र केवल चुनाव के दौरान के तीन महीनों तक है, पूरे साल नहीं। आगे बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगालियों द्वारा निभाई गई भूमिका को भुलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाली भाषा ही नहीं है, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किस भाषा में लिखे गए है? वे चाहते है कि लोग स्वतंत्रता संग्राम में बंगालियों की ऐतिहासिक भूमिका को भूल जाएं। हम इस भाषाई आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे इस दौरान सीएम ममता ने बिना नाम लिए वीर सावरकर पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का एजेंट बताते हुए कहा कि उन्होंने जेल से बाहर निकलने के लिए वचन दिए था।

विकास के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त है केंद्र सरकार

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जहां उनके प्रशासन ने कई सामाजिक कल्याणकारी पहल चलाई है, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार विकास के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना लेकर आए हैं, जबकि भाजपा के पास भ्रष्टाचार भंडार है। उन्होंने केंद्र पर भाई-भतीजावाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश को लूट रही है।

अमेरिकी टैरिफ यूपी के निर्यातकों के लिए आपदा, ये सरकार की विफलता- अखिलेश

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका की ओर से लगाए गए नए शुल्क को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बृहस्पतिवार को निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसकी असफल विदेश और आर्थिक नीतियों का खामियाजा निर्यातकों, श्रमिकों और कारीगरों को भुगतना पड़ रहा है। यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र को पहले से ही गंभीर रूप धारण कर चुकी बेरोजगारी की स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए छोटे, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को समय पर सहायता और राहत देनी चाहिए।

उन्होंने कहा, भाजपा सरकार की असफल विदेश व आर्थिक नीतियों का खामियाजा निर्यातक, मजदूर, कारीगर क्यों भुगतें। सरकार समय रहते सहायता व राहत दे नहीं तो पहले से विकराल बेरोजगारी की समस्या विकट रूप धारण कर लेगी। जब सरकार अरबपतियों पर मेहरबान हो सकती है तो लघु मध्यम व सूक्ष्म उद्योगों पर क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर व्यापारियों और निर्माताओं के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा जाए तो व्यापार वापस आए। उन्होंने श्रमिकों की स्थिति पर आधारित एक खबर का वीडियो भी पोस्ट किया। भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड फैसला बुधवार को लागू हो गया। रूस से कच्चा तेल खरीदने का हवाला देते हुए भारत पर यह शुल्क लगाया गया है। ट्रंप ने समझौते पर बातचीत के लिए 21 दिन का समय दिया था जो मंगलवार को समाप्त हो गया।

50फीसदी अमेरिकी टैरिफ पर योग गुरु रामदेव का बहिष्कार का आह्वान

नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन द्वारा 27 अगस्त से भारत पर 25फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद, योग गुरु रामदेव ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस कदम को राजनीतिक धौंस, गुंडागर्दी और तानाशाही बताते हुए, भारतीय नागरिकों से अमेरिकी कंपनियों और ब्रांडों का पूरी तरह से बहिष्कार करने का आग्रह किया है। रामदेव ने कहा कि पेप्सी, कोका-कोला, सबवे, केएफसी, और मैकडॉनल्ड्स जैसे अमेरिकी ब्रांडों का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। उनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में अराजकता फैल जाएगी और वहां महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि ट्रंप को खुद ये टैरिफ वापस लेने पड़ सकते हैं। रामदेव के अनुसार, ट्रंप ने भारत के खिलाफ जाकर एक बहुत बड़ी गलती की है।

पंजाब में बाढ़ का संकट, चपेट में आए ये 40 गांव

अमृतसर। रावी नदी में आई बाढ़ से पंजाब के 40 और गांव चपेट में आ गए हैं। जानकारी के अनुसार, अजनाला तहसील के लगभग 40 गांवों के लोग रावी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी और जिला पुलिस प्रमुख मनिंदर सिंह के नेतृत्व में आज सुबह 4 बजे से फिर से राहत कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें नागरिक प्रशासन के अलावा पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर रोहित गुप्ता, एसडीएम अमृतसर गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, जिला राजस्व अधिकारी नवकीरत सिंह, जिला पंचायत अधिकारी संदीप मल्होत्रा अपनी-अपनी टीमों के साथ राहत कार्य में लगे हुए हैं। ये टीमें सेना के एटीओआर वाहनों, नावों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से बाढ़ग्रस्त गांवों और शिविरों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। अनुमान है कि बाढ़ के कारण लगभग 14000 लोग प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि 27 अगस्त की सुबह घुस्सी तटबंध को तोड़कर पानी आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ गया था। कल पूरा दिन लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में बीता। देर रात तक डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी, जिला पुलिस प्रमुख मनिंदर सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर रोहित गुप्ता लोगों को पानी में डूबे घरों से बाहर निकालने के लिए जुटे रहे। आज 28 अगस्त को सुबह 4 बजे डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी और अतिरिक्त ड्यूटी कमिश्नर रोहित गुप्ता अपनी टीमों के साथ अमृतसर से दोबारा रवाना हुए। रमदास, जहां से कल तक गाड़ियों का काफिला निकलता था, आज रास्ता बंद कर दिया गया है।

गाड़ियां वहीं खड़ी कर दी गईं और अधिकारी-कर्मचारी ट्रैक्टरों पर आगे बढ़ गए और डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में जवानों को साथ लेकर गए ताकि लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। कल रात की गई मेहनत की बदौलत आज सुबह सेना के जवान भी पहुंच गए। उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा वाहनों के फंसने की स्थिति में एटीओआर वाहन, नावें और क्रेन लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है और इसका नेतृत्व खुद डिप्टी कमिश्नर कर रहे है। जिला प्रशासन ने गांवों से लाए गए लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की है। जिला पंचायत अधिकारी संदीप मल्होत्रा ने बताया कि इस पानी के कारण घोणेवाल, माछीवाल, निसोके, पंजगराईं वाला, घुमराईं, रोखेवाल, दरिया मूसा, मलकपुर, गिलां वाली, बेदी छन्ना, चहरपुर, कमीरपुरा, बल लभे दरिया, साहोवाल, बाजवा, खई सिंगारपुरा, जगदेव खुर्द, चकवाला, भैणी गिलां, नंगल अंब, गालिब, भदाल, समराई, सुफिया, दुजोवाल, लंगरपुर, मलकपुर, पंडोरी, खटरा, रमदास और मोहम्मद गांव प्रभावित हुए हैं।

प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों पर भड़के चिराग पासवान, कांग्रेस और राजद को खूब सुनाया

पटना। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भड़क गए हैं। चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में, हर किसी की अपनी राय और वोट है, और मतभेदों के कारण, कोई भाषाओं की गरिमा को कम नहीं कर सकता।

भारतीय भाषाओं में शब्दों का इतना अच्छा संग्रह है और कोई भी गरिमापूर्ण शब्दों का उपयोग करके तीखे हमले कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिराग पासवान ने कहा कि अगर आपको प्रधानमंत्री के काम और सरकारी नीतियों से कुछ समस्या है, तो आप ऐसा कर सकते है। लेकिन आप प्रधानमंत्री के परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो सार्वजनिक जीवन से दूर है। उन्होंने स्थानीय गुंडों की तरह बात की है, और ये राजद की परंपरा है, जिसने 1990 के दशक से हमारे बिहार को बदनाम किया है, और अब तक हम अपनी खोई हुई विरासत और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आपके गुंडे जो प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर वो शहर में लगे मंच से ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कल्पना ही की जा सकती है कि वो घर पर या गांव जाते समय क्या शब्द बोलते होंगे। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के परिवार से क्या लेना-देना जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है? उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मेरे साथ भी ऐसा ही किया था... कांग्रेस और राजद दोनों ही इतनी पुरानी पार्टियां है, उन्हें कम से कम ये तो समझ आ जाना चाहिए कि मां, सरकार का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को बिहार की एक रैली के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। इस वीडियो में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इंडिया ब्लॉक पर हमला तेज करते हुए दावा किया कि मतदाता अधिकार यात्रा बेहद अशोभनीय थी और अपमान, घृणा और अश्लीलता की सभी सीमाओं को पार कर गई।

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना लागू : सीएम नायब सैनी का एलान, 25 सितंबर से महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये

चंडीगढ़।

हरियाणा में दीन दयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने की घोषणा कर दी गई है। योजना 25 सितंबर से लागू होगी। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका एलान किया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में सीएम सैनी ने कहा कि कैबिनेट ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारम्भ होगा। सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 25 सितंबर को हरियाणा की 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में, उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। आने वाले समय में, चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का या विवाहित महिला के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल

निवासी होना अनिवार्य होगा।

परिवार में महिलाओं की संख्या पर प्रतिबंध नहीं

इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि एक परिवार में तीन महिलाएं हैं, तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी नौ योजनाओं, जिनमें आवेदिका को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित मरीजों (महिलाओं), सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिमिया और स्किन सेल से पीड़ित मरीजों को पहले से पेंशन मिल रही है। इन महिलाओं को इस योजना का भी अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी उस दिन वे ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आने वाले 6 या 7 दिनों में योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे। साथ ही एक ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। हर संभावित पात्र महिला को हम एसएमएस करेंगे कि आप उस ऐप पर आवेदन कर दें। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा।